

रजिस्टर्ड नं० एल०-३३/एम० एम०/१३-१४/९६



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(अमाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, ११ मार्च, १९९६/ २१ फाल्गुन, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-४, ११ मार्च, १९९६

संख्या १-२५/९६-वि० स०—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य मंचालन नियमावली, १९७३ के नियम १३५ के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक ४) विधेयक, १९९६ (१९९६ का विधेयक)

८५०-राजपत्र/९६-११-३-९६—१,२२५.

(९५९)

मूल्य : १ रुपया।

संख्यांक 12) जो दिनांक 11 मार्च, 1996 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, एवं सर्वसाधारण की सूचनार्थ असाधारण राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

के० एल० वर्मा
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 1996

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से, वित्तीय वर्ष 1991-92 में, कतिपय सेवाओं पर, उन सेवाओं के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए कतिपय रकम के विनियोजन को प्राधिकृत करने का उपबन्ध करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के सैतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 4) संक्षिप्त नाम । अधिनियम, 1996 है ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राशियाँ, जिनका योग 10,02,03,71,324 रुपये (दस अरब, दो करोड़, तीन लाख, ईकतहर हजार, तीन सौ चौबीस रुपये) है, वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए प्राधिकृत या मंजूर की गई रकम से अधिक व्यय की गई रकम को पूरा करने के लिए संदत्त किए जाने और उपबन्धन के लिए प्राधिकृत समझी जाएंगी ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 1991-92 के लिए कतिपय व्ययों को पूरा करने के लिए 10,02,03,71,324 रुपये की और राशि प्राधिकृत करना ।

3. इस अधिनियम के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपबन्धन के लिए प्राधिकृत समझी जाने वाली राशियाँ, वित्तीय वर्ष, 1991-92 से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त, सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित समझी जाएंगी ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
		रुपये	रुपये	रुपये
3	न्याय प्रणामन (राजस्व)	—	30,936	30,936
9	चिकित्सा और परिवार कल्याण (राजस्व)	66,20,897	—	66,20,897
10	लोक निर्माण (राजस्व)	16,15,40,708	—	16,15,40,708
	(पूजी)	7,60,743	—	7,60,743
12	मिचाई और बाढ़ नियंत्रण (राजस्व)	26,64,598	—	26,64,598
14	पशु पालन और दुग्ध विकास (राजस्व)	6,39,553	—	6,39,553
16	वन और वन्य जीवन (राजस्व)	—	1	1
17	सड़कें और पुल (राजस्व)	7,33,638	—	7,33,638
18	आपूर्ति उद्योग और खनिज (राजस्व)	22,28,164	—	22,28,164
	(पूजी)	68,45,607	—	68,45,607
20	ग्रामीण विकास (पूजी)	252	—	252
22	खाद्य और भाण्डागारण (राजस्व)	1,42,290	—	1,42,290
23	जल और विद्युत विकास (राजस्व)	28,00,000	—	28,00,000
24	लेखन सामग्री और मुद्रण (पूजी)	1,57,789	—	1,57,789
25	सड़क, जल और नागर विमानन (पूजी)	21,23,205	—	21,23,205
26	पर्यटन और आतिथ्य संगठन (पूजी)	2,33,913	—	2,33,913
27	श्रम और रोजगार (पूजी)	1,84,993	—	1,84,993
28	जलापूर्ति, सफाई, आवागम और नगर विकास (राजस्व)	3,07,60,338	—	3,07,60,338
29	वित्त (पूजी)	—	9,80,19,03,699	9,80,19,03,699
	जोड़	21,84,36,688	9,80,19,34,636	10,02,03,71,324

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड (1) के साथ पठित, अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान अनुदान और विनियोग से अधिक किए गए व्यय को पूरा करने के लिए और अधिक धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
11 मार्च, 1996.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग, फाईल नं० फिन ए०-सी (2) 1/93-II]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल; हिमाचल प्रदेश विनियोग (संज्ञांक 4) विधेयक, 1996 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 12 of 1996.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4)

BILL, 1996

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to provide for the authorisation of appropriation of certain amount out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet the amount spent on certain services for the financial years 1991-92 in excess of the amount authorised or granted for those services for that year.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1996.

Authorisation of a further sum of Rs. 10,02,03,71,324 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh to meet certain expenditure for the financial year 1991-92.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 10,02,03,71,324 (one Thousand and two crores, three lakh, seventy one thousand, three hundred and twenty four) shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent for defraying the charges in respect of the services specified in the column (2) of the Schedule during the financial year 1991-92 in excess of the amount authorised or granted for those services and for that year.

Appropriation.

3. The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year 1991-92.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

1 Number of Demand	2 Services and purposes	3 Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Con- solidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
3	Administration of Justice (Revenue)	—	30,936	30,936
9	Health and Family Welfare (Revenue)	66,20,897	—	66,20,897
10	Public Works (Revenue)	16,15,40,708	—	16,15,40,708
	(Capital)	7,60,743	—	7,60,743
12	Irrigation and Flood Control (Revenue)	26,64,598	—	26,64,598
14	Animal Husbandry and Dairy Development (Revenue)	6,39,553	—	6,39,553
16	Forest and Wild Life (Revenue)	—	1	1
17	Roads and Bridges (Revenue)	7,33,638	—	7,33,638
18	Supplies, Industries and Minerals (Revenue)	22,28,164	—	22,28,164
	(Capital)	68,45,607	—	68,45,607
20	Rural Development (Capital)	252	—	252
22	Food and Warehousing (Revenue)	1,42,290	—	1,42,290
23	Water and Power Development (Revenue)	28,00,000	—	28,00,000
24	Printing and Stationery (Capital)	1,57,789	—	1,57,789
25	Road, Water Transport and Civil Aviation (Capital)	21,23,205	—	21,23,205
26	Tourism and Hospitality Organisation (Capital)	2,33,913	—	2,33,913
27	Labour and Employment (Capital)	1,84,993	—	1,84,993
28	Water Supplies, Sanitation, Housing and Urban Development (Revenue)	3,07,60,338	—	3,07,60,338
29	Finance (Capital)	—	9,80,19,03,699	9,80,19,03,699
	Total ..	21,84,36,688	9,80,19,34,636	10,02,03,71,324

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of Clause (1) of Article 204 read with Clause (1) of Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure on the account of expenses in excess of grant and appropriations for the financial year 1991-92.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 11th March, 1996.

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[Finance Department, File No. Fin. A-C(2) 1/93-II]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 1996 recommends under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the aforesaid Bill in the Legislative Assembly.